The Times Of India dt 21/6/2016 P8

Mustard set to become 1st GM food crop to get nod

TIMES NEWS NETWORK

The anti-GM group has written to the Union environment and science & technology ministers demanding rejection of the proposal to commercialise GM mustard and also for the scrapping of the regulator

New Delhi: The central regulator on genetically modified crops, the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), is poised to give its approval for commercial release of GM mustard.

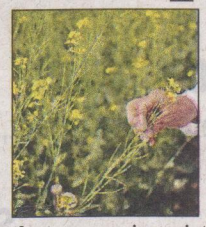

It examined the issue on Monday in a specially convened meeting where it reviewed additional information provided to it by the Delhi University's institution that developed the particular transgenic variety of the oilseed. The regulator also heard the contention of representatives of anti-GM groups which have been opposing its intended move to clear the transgenic variety.

Though the GEAC, comprising government officials and experts from outside, did not take its final call on the issue, during the meeting the members are learnt to have expressed satisfaction over the evidence of scientific field trials submitted to them.

The GEAC's lenient view towards the transgenic mustard was, however, strongly opposed by the anti-GM activists, led by farm activist Kavitha Kuruganti, on Monday. They said that the regulator chose not to give a delegation from the Coalition for a GM-Free India enough time for presentations "that would have revealed the level of fraud that underpinned DMH-11 R&D and testing".

मप्र में इस बार दलहनी फसलों की तरफ किसानों का रुझान

इंदौर, 20 जून (भाषा)। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उगाने वाले मध्य प्रदेश में मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान किसानों के इस तिलहनी फसल के मुकाबले अरहर (तुअर) जैसी दलहनी फसलों को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से बुआई के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बुआई लक्ष्य पांच फीसद घटा दिया है, जबकि दलहनी फसलों के लक्षित रकबे में 26.5 फीसद वृद्धि की है।

प्रदेश के कृषि विभाग के संचालक मोहनलाल मीणा ने सोमवार को बताया कि सूबे में पिछले तीन खरीफ सत्रों के दौरान सूखे और अतिवृष्टि जैसे मौसमी कारणों से सोयाबीन उगाने वाले किसानों ने खासा नुकसान उठाया था। इसलिए इस बार सोयाबीन के प्रति किसानों का विश्वास कम हुआ है, जबकि उपज की अपेक्षाकृत अच्छी कीमत मिलने के कारण दलहनी फसलों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा है। किसानों के इस रुझान को देखते हुए हमने मौजूदा खरीफ सत्र में सोयाबीन का बुआई लक्ष्य घटाकर 56 लाख हेक्टेयर कर दिया है और दलहनी फसलों के लक्षित रकबे को बढ़ाकर 21.5 लाख हेक्टेयर कर दिया है। केंद्र सरकार की भी नीति है कि दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाए।

मीणा ने बताया कि 2015-16 के खरीफ सत्र में सोयाबीन का रकबा करीब 59 लाख हेक्टेयर रहा था, जबकि लगभग 17 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई थीं। पिछले सत्र में बुआई के बाद लंबे अंतराल तक मानसूनी बारिश नही होने से खासकर सोयाबीन की फसल को बड़ा नुकसान हुआ था। सोयाबीन मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है और किसानों में 'पीले सोने' के रूप में मशहूर है।

इस बीच, प्रसंस्करणकर्ताओं के संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के रकबे में पांच फीसद की अनुमानित कमी से सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाठक ने कहा कि पिछले खरीफ सत्र में मौसम की मार के कारण सूबे में सोयाबीन की पैदावार काफी कम रही थी। इस बार मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, जिससे इस तिलहनी फसल की पैदावार बढ़ सकती है। इस स्थिति में सोयाबीन के रकबे में कमी

जनसत्ता P10
दिनांक 21/6/2016

Rajshree
21-6-2016